

II. समग्र माँग

समग्र माँग, जिसमें वर्ष 2008-09 में काफी नरमी आयी थी, वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में भी शिथिल बनी रही। निजी उपभोग और निवेश माँग में वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में गिरावट बनी रही, जिसमें से निजी उपभोग ने हाल के वर्षों में न्यूनतम तिमाही वृद्धि दर्ज की। सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि, जो वर्ष 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाही में अधिक हुई थी, वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में कम हुई, लेकिन यह दो अंकों में बनी रही। अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक, यथा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक ऊँचाई पर थे, जो मंदी-प्रेरित राजस्व प्राप्तियों में कमी और विस्तारक राजकोषीय स्वरूप से संगति रखते हुए सरकारी खर्च में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। कंपनी क्षेत्र के आँकड़े वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान विक्रय-वृद्धि में संयमित कमी का संकेत देते हैं, हालाँकि लाभ-मार्जिन में सुधार हुआ।

II.1 विश्वास सरणी के माध्यम से प्रचालित वैश्विक संकट के संसर्ग ने निजी उपभोग और निवेश माँग को शिथिल किया है और इसका प्रभाव वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में भी बना रहा, जब निजी उपभोग माँग में वृद्धि सबसे न्यून स्तर तक कम हो गयी। जबकि माँग पक्ष की ओर से मापी गयी वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान 6.0 प्रतिशत पर पूर्ववर्ती दो तिमाहियों की तुलना में अधिक थी, यह सुधार अधिकतर निर्यात की

तुलना में आयात-संकुचन के परिणामस्वरूप हुआ, जिसने जीडीपी में निवल निर्यात के हिस्से को ऋणात्मक से धनात्मक कर दिया। माँग का घरेलू घटक वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान दुर्बल बना रहा। निजी उपभोग माँग में तेज गिरावट आकर वह 1.6 प्रतिशत रह गयी, जो हाल के वर्षों में न्यूनतम वृद्धि है। यह गिरावट समग्र माँग (अर्थात् वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान 55.6 प्रतिशत) में निजी उपभोग माँग के उच्च हिस्से के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। निवेश माँग में वृद्धि, जिसका अनुमान सकल अचल पूँजी निर्माण की स्थिति से लगाया जा सकता है, पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में दर्ज की गयी वृद्धि के आधे से भी कम थी। सरकारी उपभोग खर्च में वृद्धि दो अंकों में बनी रही, लेकिन यह वर्ष 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाहियों में देखी गयी उच्च वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। समग्र माँग में इसके न्यून हिस्से को देखते हुए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय समग्र उपभोग व्यय पर निजी उपभोग और निवेश माँग के प्रतिकूल प्रभाव की पूरी तरह क्षतिपूर्ति नहीं कर सका। केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक, यथा, राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में बजट अनुमान के अनुपात में कम रहे। कंपनी कार्यनिष्पादन में धीमी गति बनी रही और माँग में कमी का प्रभाव वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में विक्रय-वृद्धि में आयी कमी में देखा जा सकता है। तथापि, सकल लाभ लगातार दो तिमाहियों तक कम रहने के बाद बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण था न्यून निविष्टि और परिचालन लागत और उच्चतर अस्थायी आय। निर्यात में निरंतर गिरावट के बावजूद निवल निर्यात धनात्मक हुआ, जो आयात में तेजी से संकुचन होने के कारण हुआ।¹

घरेलू माँग

II.2 निजी उपभोग व्यय और निवेश के रूप में घरेलू माँग में, जो वर्ष 2008-09 में शिथिल हो गयी थी, वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में गिरावट बनी रही, जो द्रुत समुत्थान के अवरोधक के रूप में दुर्बल घरेलू माँग को प्रतिबिंबित करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के लिए जारी किये गये आँकड़ों के अनुसार निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल अचल पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने वृद्धि में वर्ष 2008-09 की तदनुकूल अवधि की तुलना में तेज गिरावट दर्ज की (सारणी 2.1 और चार्ट II.1)। अपूर्ण मानसून ने वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही से निजी उपभोग माँग को ग्रामीण माँग पर प्रतिकूल प्रभाव के माध्यम से और कमजोर किया होगा। क्रेडिट कार्ड और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित ऋण में गिरावट भी दुर्बल उपभोग माँग के बने रहने की ओर इशारा करते हैं।

II.3 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि, जो वर्ष 2008-09 में अन्य क्षेत्रों में संकुचन के प्रभाव को बचाने के उद्देश्य से नीतिचालित राजकोषीय प्रेरक तत्वों के प्रत्युत्तर में काफी बढ़ी थी, ने वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की, हालाँकि यह पिछली दो तिमाहियों की तुलना में गिरावट की द्योतक है।

¹ वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी में रिपोर्ट किये गये निवल निर्यात के आँकड़े (स्थिर मूल्यों पर) भुगतान संतुलन (बीओपी) में पहली तिमाही के लिए अंकित निवल निर्यात आँकड़ों से भिन्न हैं, जिसका कारण है (क) बीओपी के आँकड़ों को जीडीपी आँकड़ों के बाद जारी किया जाना और इसलिए सेवाओं के संबंध में अनुमान का उपयोग जीडीपी आँकड़ों में किया जाना और (ख) स्थिर मूल्य पर निवल निर्यात के आँकड़े प्राप्त करने के लिए अपस्फीतिकारकों का उपयोग करना, क्योंकि वर्तमान मूल्यों पर मुख्यतया अंतर (क) के कारण होते हैं।

सारणी 2.1: जीडीपी का मांग पक्ष (1999-2000 मूल्यों पर)

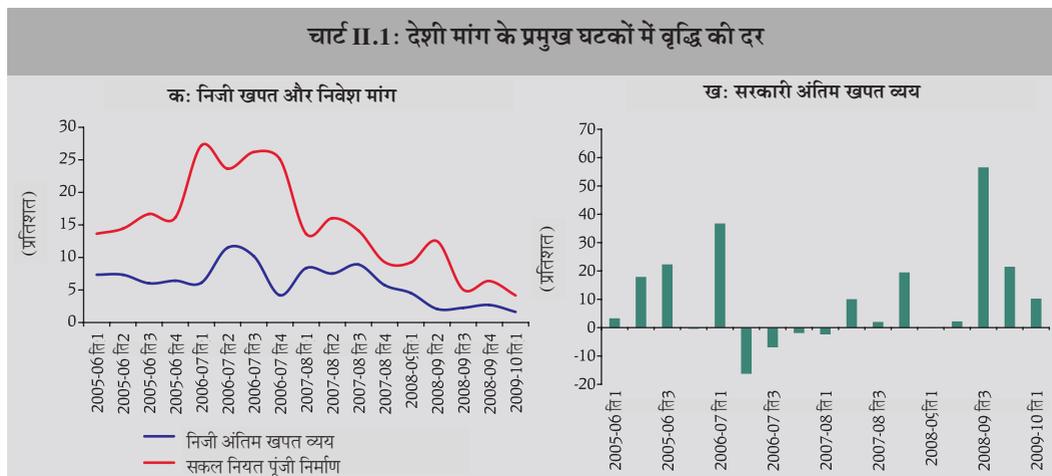
(प्रतिशत)							
मद	2007-08*	2008-09#	2008-09				2009-10
			ति1	ति2	ति3	ति4	
1	2	3	4	5	6	7	8
वृद्धि दर							
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	9.1	6.1	8.2	7.8	4.8	4.1	6.0
कुल खपत व्यय	8.3	5.4	3.8	2.1	9.0	6.1	2.8
(i) निजी	8.5	2.9	4.5	2.1	2.3	2.7	1.6
(ii) सरकारी	7.4	20.2	-0.2	2.2	56.6	21.5	10.2
सकल अचल पूँजी निर्माण	12.9	8.2	9.2	12.5	5.1	6.4	4.2
स्टॉक में परिवर्तन	51.7	2.9	6.0	5.6	1.4	-0.9	3.2
निर्यात	2.1	12.8	25.6	24.3	7.1	-0.8	-10.9
घटाया:आयात	6.9	17.9	27.4	35.3	21.7	-5.7	-21.2
सापेक्षिक हिस्सा							
कुल खपत व्यय	66.9	66.5	67.5	63.7	69.9	64.8	65.5
(i) निजी	57.2	55.5	58.0	55.5	57.4	51.4	55.6
(ii) सरकारी	9.8	11.1	9.6	8.3	12.5	13.4	9.9
सकल अचल पूँजी निर्माण	31.6	32.2	32.2	34.5	30.9	31.6	31.6
स्टॉक में परिवर्तन	3.1	3	3.2	3.2	2.9	2.9	3.1
निवल निर्यात	-4.3	-5.8	-1.3	-10.5	-8.5	-2.9	1.6
ज्ञापन: (करोड़ रुपए)							
बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद	34,02,716	36,09,425	8,33,631	8,49,247	9,45,121	9,81,427	8,83,489
* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान							
नोट: चूंकि प्रमुख मदे ही सारणी में शामिल की गई हैं, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।							
स्त्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।							

II.4 हिस्से के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय घट कर 55.6 प्रतिशत रह गया, जबकि यह वर्ष 2008-09 की तदनुकूल अवधि के दौरान 58.0 प्रतिशत था (सारणी 2.1)।

संयुक्त बजट-निर्धारित वित्त: 2009-10

II.5 वर्ष 2009-10 के लिए बजट-निर्धारित केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त के विहगावलोकन से पता

चार्ट II.1: देशी मांग के प्रमुख घटकों में वृद्धि की दर



चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक उच्च स्तर पर बने रहेंगे, जैसा कि वे वर्ष 2008-09 में थे (सारणी 2.2)। संयुक्त घाटे में यह वृद्धि आर्थिक मंदी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा अंगीकृत विस्तारक राजकोषीय दृष्टिकोण के बने रहने को प्रतिबिंबित करती है। हालाँकि कुल व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष से कुछ कम होगी, बजट में विकासेतर घटक को काफी बढ़ाया गया है। इस प्रकार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय आगे और बढ़ेगा। दूसरी ओर, कर-संग्रह में वृद्धि अप्रत्यक्ष करों में कटौती और आर्थिक वृद्धि में शिथिलता के कारण कम होगी। इसके परिणामस्वरूप, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संयुक्त राजस्व प्राप्तियों को बजट में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में कम रखा गया है, हालाँकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप

में करेतर प्राप्तियाँ 3.8 प्रतिशत से बढ़ कर 4.2 प्रतिशत हो जायेंगी। इसके फलस्वरूप वर्ष 2009-10 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संयुक्त राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 1.1 और 1.3 प्रतिशत अंक बढ़ कर क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत हो जायेगा।

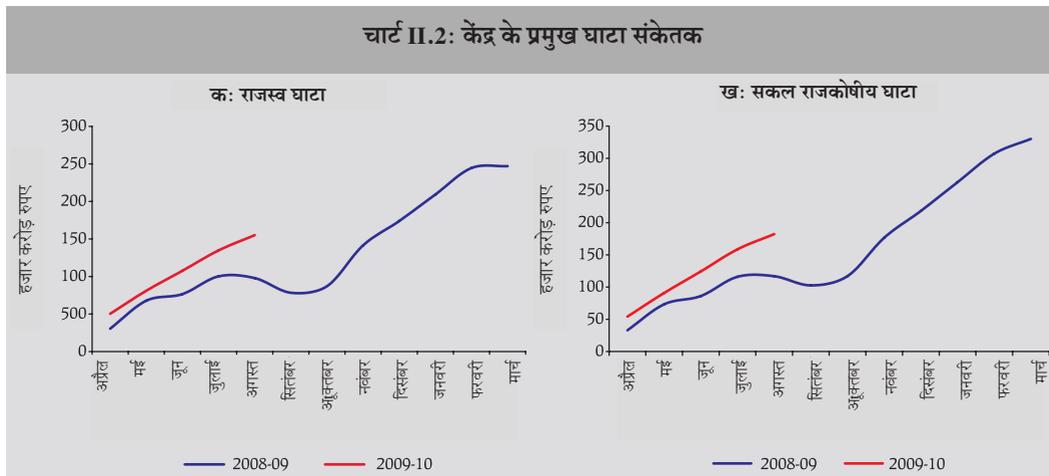
केंद्र सरकार का वित्त

II.6 वर्ष 2009-10 के पहले पाँच महीनों के लिए केंद्र सरकार के वित्त के संबंध में महालेखानियंत्रक से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), दोनों ही मात्रा की दृष्टि से पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में काफी अधिक थे, लेकिन वे बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में कम थे (चार्ट II.2 क और ख तथा सारणी 2.30।

सारणी 2.2: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

सारणी 2.2: प्रमुख राजकोषीय संकेतक				
(जीडीपी का प्रतिशत)				
वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5
केंद्र				
2007-08	-0.9	1.1	2.7	60.1
2008-09 सं.अ.	2.5 (2.6)	4.4 (4.6)	6.0 (6.2)	58.9
2009-10 ब.अ.	3.0	4.8	6.8	59.7
राज्य				
2007-08 #	-0.6	-0.9	1.5	27.8
2008-09 # सं.अ.	0.7	-0.1	2.7	27.1
2009-10 # ब.अ.	1.4	0.6	3.4	27.5
संयुक्त				
2007-08	-1.3	0.2	4.2	75.1
2008-09 सं.अ.	3.5	4.4	8.9	74.7
2009-10 ब.अ.	4.5	5.5	10.2	76.6
सं.अ.: संशोधित अनुमान		ब.अ.: बजट अनुमान		
* : ऐतिहासिक विनिमय दरों पर बाह्य देयताएं शामिल।				
# : आंकड़े 27 राज्य सरकारों के हैं जिनमें से दो लेखा अनुदान हैं।				
टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।				
2. कोष्ठकों के आंकड़े अर्न्तम लेखों से संबंधित हैं।				
3. तेल/एफसीआइ/उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांडों को छोड़कर जिसकी राशि 2007-08 में जीडीपी का 0.8 प्रतिशत, 2009-10 में 1.8 प्रतिशत तथा 2009-10 में 0.2 प्रतिशत रही है।				

चार्ट II.2: केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक



II.7 अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त का पैटर्न यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में निवल कर-राजस्व अप्रैल-अगस्त 2008 की तुलना में कम था, जिसका कारण यह था कि इन पाँच महीनों में से प्रत्येक महीने में सकल कर-राजस्व में भारी गिरावट आयी,

जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। आर्थिक मंदी को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्यक्ष करों, यथा, निगम कर और आयकर के अंतर्गत वसूली अप्रैल-अगस्त 2009 में कम हो कर एक अंकीय वृद्धि वाली रह गयी, अप्रैल-अगस्त 2008 में इसमें काफी वृद्धि

सारणी 2.3 : अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान केन्द्र सरकार के वित्त

मद	अप्रैल-अगस्त (करोड़ रुपए)		निम्नोक्त वर्षों के बजट अनुमान का प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2008	2009	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व प्राप्तियां	1,61,511	1,57,198	26.8	25.6	24.5	-2.7
i) कर राजस्व	1,25,436	1,06,837	24.7	22.5	26.2	-14.8
ii) करेतर राजस्व	36,075	50,361	37.7	35.9	18.6	39.6
2. ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	1,203	3,835	8.2	71.7	-69.5	-
3. योजनेतर व्यय	1,92,962	2,45,275	38.0	35.3	18.0*	27.1
जिसमें से:						
(i) ब्याज अदायगी	65,841	72,133	34.5	32.0	4.4	9.6
(ii) रक्षा	24,811	41,129	23.5	29.0	6.1	65.8
(iii) प्रमुख सब्सिडियां	51,780	54,193	77.2	51.1	72.4	4.7
4. योजना व्यय	86,642	98,048	35.6	30.2	19.8	13.2
5. कुल व्यय	2,79,604	3,43,323	37.2	33.6	18.6 *	22.8
6. राजस्व व्यय	2,59,390	3,12,283	39.4	34.8	19.2	20.4
7. पूंजीगत व्यय	20,214	31,040	21.8	25.1	10.8 *	53.6
8. राजस्व घाटा	97,879	1,55,085	177.4	54.9	11.4	58.4
9. राजकोषीय घाटा	1,16,890	1,82,290	87.7	45.5	14.5	56.0
10. सकल प्राथमिक घाटा	51,049	1,10,157	-88.8	62.8	30.6	-

* : वृद्धि दर की गणना जून 2007 में भारत सरकार को अंतरित स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के अंश को घटाकर की गई है।

स्रोत : महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

दर्ज की गयी थी। जबकि इसी अवधि में आयात में तीव्र कमी के कारण सीमाशुल्क से प्राप्त राजस्व में कमी आयी, उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राजस्व में कर कटौतियों और घरेलू बिक्री में गिरावट के चलते कमी आयी। करेतर राजस्व में पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जिसमें रिजर्व बैंक से अधिशेष निधियों का अंतरण कुल करेतर राजस्व के 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार था। करेतर राजस्व की वृद्धि में काफी बढ़ोतरी होने के बावजूद राजस्व प्राप्तियों में अप्रैल-अगस्त 2009 में पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में गिरावट दर्ज की गयी।

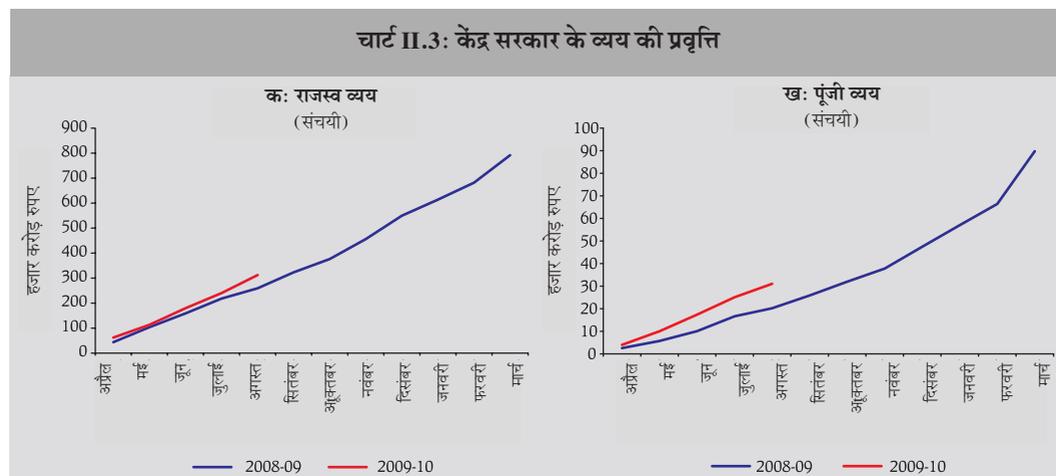
II.8 राजस्व व्यय अप्रैल-अगस्त 2008 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2009 की अवधि में उच्च दर से बढ़ा, जिसका मुख्य कारण था ब्याज भुगतान, खाद्य सहायता, प्रतिरक्षा राजस्व व्यय और पेंशन के लिए अधिक व्यय करना (चार्ट II.3 क)। जबकि उच्चतर ब्याज भुगतान वर्ष 2008-09 में लिये गये बड़े उधारों के कारण हुआ, छोटे वेतन आयोग पंचाट के अंतर्गत बढ़े हुए वेतन भुगतान ने प्रतिरक्षा और पेंशन के अंतर्गत व्यय को बढ़ा दिया। तथापि, बजट अनुमानों

के रूप में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में कम हुआ। इस प्रकार वर्ष 2009-10 के पहले पाँच महीनों में राजस्व घाटा बजट अनुमान के 54.9 प्रतिशत पर काफी कम था, जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान यह 177.4 प्रतिशत था।

II.9 अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान पूँजीगत व्यय में उच्च द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गयी (चार्ट II.3 ख)। जबकि प्रतिरक्षा पूँजीगत व्यय में लगभग तिगुनी वृद्धि दर्ज की गयी, गैर-प्रतिरक्षा पूँजीगत परिव्यय रेलवे में अधिक था। अप्रैल-अगस्त 2009 में समग्र व्यय अप्रैल-अगस्त 2008 की तुलना में बढ़ा, लेकिन यह बजट अनुमान के कम आँके जाने के कारण था। इसी अवधि में जीएफडी बजट अनुमान का 45.5 प्रतिशत था, जबकि अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान यह 87.7 प्रतिशत था। केंद्र सरकार का सकल प्राथमिक घाटा वर्ष 2009-10 के पहले पाँच महीनों में बढ़ कर बजट अनुमान के 62.8 प्रतिशत पर दर्ज किया गया।

II.10 नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (अंत-सितंबर 2009 तक) के दौरान प्रत्यक्ष करों की वसूली में पिछले राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना

चार्ट II.3: केंद्र सरकार के व्यय की प्रवृत्ति



में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। जबकि कंपनी कर की वसूली में 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, वैयक्तिक आयकर (प्रतिभूति लेन देन कर सहित) के अंतर्गत वसूली में 0.38 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह रिपोर्ट की गयी है कि अग्रिम कर की वसूली वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही के दौरान पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में अधिक हुई।

राज्य वित्त : 2009-10²

II.11 वर्ष 2007-08 तक परिलक्षित राजकोषीय सुधार और समेकन वर्ष 2008-09 के दौरान मंदी के कारण कुछ हद तक पलट गया। राज्य सरकारों का समेकित राजस्व लेखा जो पिछले तीन वर्षों तक अधिशेष में रहा था, वर्ष 2009-10 के दौरान बजट में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के घाटे में बदल जाने का अनुमान है, जिसका कारण है उनकी अपनी कर वसूली में शिथिलता और केंद्र से अंतरण के साथ अनेक राज्य सरकारों द्वारा छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिक व्यय करने की प्रतिबद्धता। इसके परिणामस्वरूप, बजट में जीएफडी बढ़कर जीडीपी का 3.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2008-09 में यह 2.7 प्रतिशत था (आरई)। बजट में वर्ष 2009-10 में समेकित प्राथमिक घाटे के बढ़ कर जीडीपी के 1.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2008-09 में यह 0.7 प्रतिशत था (आरई)(सारणी 2.2)।

II.12 अर्थव्यवस्था में समग्र माँग को प्रेरित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अनुमति दी कि वे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त बाजार उधार ले सकते हैं और इस प्रकार वर्ष 2009-10 के दौरान जीएफडी की सीमा बढ़ा

² राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित, जिनमें से दो लेखा अनुदान हैं।

कर जीएसडीपी के 4.0 प्रतिशत कर दी गयी (वर्ष 2008-09 के दौरान जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत)। तथापि, समेकित स्तर पर राज्यों का समग्र व्यय वर्ष 2009-10 के बजट में 12.2 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है (बीई), जबकि यह वर्ष 2008-09 के दौरान 26.0 प्रतिशत था।

कंपनी कार्यनिष्पादन

II.13 चुनिंदा गैर वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के कार्यसंपादन के विश्लेषण ने यह दर्शाया है कि बिक्री में वृद्धि, जो वर्ष 2008-09 की पहली और दूसरी तिमाहियों में काफी अधिक हुई थी, घटती माँग और विश्वास के चलते सितंबर 2008 के बाद तेजी से कम होती गयी। माँग में सुस्ती और न्यून वस्तु-कीमतों ने बिक्री में वृद्धि को प्रभावित किया, जो वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में ऋणात्मक हो गयी (सारणी 2.4)। आय में कमी होने के बावजूद कंपनियाँ कुल मिला कर अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने में समर्थ हुईं, जिसका कारण था उच्चतर लाभ मार्जिन, जो प्रमुख रूप से न्यून निविष्टि लागत, ब्याज भुगतान में काफी गिरावट आने, विदेशी मुद्रा से संबंधित हानि के कम होने, और अस्थायी अन्य आय में अधिक वृद्धि होने से प्रेरित था। वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में मार्जिन में सुधार ने कंपनी क्षेत्र द्वारा आर्थिक स्थिति में मंदी के प्रत्युत्तर में आरंभ की गयी लागत घटाने की पहल को भी प्रतिबिंबित किया, जिसने परिचालन व्यय को नियंत्रित करने में मदद की। पहली तिमाही में धीमी बिक्री और लाभ संबंधी उन्नत कार्यनिष्पादन भी अंशतः आधार प्रभाव के कारण हुआ, क्योंकि निजी कंपनी क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि के दौरान बिक्री में 29.3 प्रतिशत वृद्धि की पृष्ठभूमि में लाभ में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी।

II.14 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार विनिर्माण के क्षेत्र में कंपनियों के लिए बिक्री में कमी और लाभ संबंधी

सारणी 2.4 : कंपनी क्षेत्र-वित्तीय कार्यनिष्पादन

(वृद्धि दर/ अनुपात प्रतिशत में)

मद	2007-08	2008-09	2008-09				2009-10
			ति1	ति2	ति3	ति4	
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री	18.6	17.2	29.3	31.8	9.5	1.9	-0.9
अन्य आय*	62.2	6.6	-8.4	-0.6	-4.8	39.4	50.2
व्यय	19.4	19.5	33.5	37.5	12.6	-0.5	-4.4
मूल्यहास प्रावधान	15.7	17.4	15.3	16.5	16.8	19.6	21.5
सकल लाभ	24.9	-4.2	11.9	8.7	-26.7	-8.8	5.8
ब्याज भुगतान	29.4	57.3	58.1	85.3	62.9	36.5	3.7
करोत्तर लाभ	26.0	-18.4	6.9	-2.6	-53.4	-19.9	5.5
चुनिंदा अनुपात							
बिक्री के प्रति बिक्रेय माल में परिवर्तन	1.9	0.4	2.9	2.2	-1.7	-1.8	0.6
बिक्री के प्रति सकल लाभ	14.9	13.3	14.5	13.5	11.0	13.7	15.7
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	9.8	8.1	9.7	8.6	5.3	8.1	10.2
बिक्री के प्रति ब्याज	2.5	3.1	2.4	2.9	3.8	3.2	2.8
सकल लाभ के प्रति ब्याज	16.8	23.6	16.8	21.5	34.6	23.3	18.0
ब्याज की व्याप्ति (गुणांक)	5.8	4.2	6.0	4.6	2.9	4.3	5.6

* : यदि स्पष्ट रूप से रिपोर्ट न किया गया हो तो असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है।

टिप्पणी: 1. 2007-08 के आंकड़े लेखा परीक्षित वित्तीय लेखों पर आधारित हैं; 2008-09 और 2009-10 के आंकड़े चुनिंदा गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमि. कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।
2. वृद्धि दरें संदर्भाधीन अवधि के लिए कंपनियों के सामान्य सेट के लिए पिछले साल की तदनु रूप अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में हैं।

कार्यनिष्पादन सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा क्षेत्रों की कंपनियों की तुलना में अधिक स्पष्ट था। विनिर्माण कंपनियों की समग्र बिक्री, जो वर्ष 2008-09 की पहली दो तिमाहियों में बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में तीसरी तिमाही में कम हो गयी थी, में वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में थोड़ी कमी दर्ज की गयी, जो उत्पाद-कीमतों में मंदता और धीमी माँग-वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। निवल लाभ मार्जिन, जिसे बिक्री की तुलना में निवल आय के अनुपात के रूप में मापा गया है, जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए सबसे कम था, और जो वर्ष वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही में घट कर 5.0 प्रतिशत से भी कम रह गया था, उसमें सुधार हुआ और वह वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में 9.2 प्रतिशत हो गया, क्योंकि

परिचालन संबंधी स्थिति में सुधार हुआ और ब्याज बहिर्वाह काफी हद तक कम हो गया। तुलनात्मक रूप में देखा जाये, तो सेवा-क्षेत्र की कंपनियों ने वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में बिक्री में गिरावट के बावजूद लाभ मार्जिन को न्यूननाधिक बनाये रखा।

II.15 चुनिंदा गैर वित्तीय सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (तेल और तेल से इतर) ने वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में बिक्री में 24.3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद निवल लाभ में 20.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। समग्र कार्यनिष्पादन तेल कंपनियों के कार्यनिष्पादन से प्रेरित था, जिनके लिए निवल लाभ मार्जिन में काफी सुधार हुआ, जिसका कारण एक ओर ब्याज के भुगतान में कमी होना, कच्चे माल और स्टाफ-खर्च कम होना और दूसरी ओर अन्य आय में काफी

बढ़ोतरी होना था। तथापि, तेल से इतर सरकारी कंपनियों के लिए परिचालन मार्जिन में कमी आयी, क्योंकि बिक्री की तुलना में व्यय अधिक हुआ।

बाह्य माँग

II.16 वैश्विक मंदी और विश्व व्यापार के परिमाण में कमी होने के कारण बाह्य माँग की स्थिति प्रतिकूल बनी रही, भले ही उसमें हाल में सुधार के संकेत मिले हैं। वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में भारत में वस्तु एवं सेवाओं के आयात में निर्यात से अधिक संकुचन हुआ और इसके परिणामस्वरूप निवल निर्यात, जिसका जीडीपी में योगदान पिछली तिमाहियों में ऋणात्मक था, वह धनात्मक हो गया (सारणी 2.1)। वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के बाद निर्यात के संबंध में अंशतः जानकारी वणिक् व्यापार की स्थिति से प्राप्त की जा सकती है। अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान वणिक् व्यापार घाटा 38.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ, जो अप्रैल-अगस्त 2008 में 60.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से 37.1 प्रतिशत कम था, जिसका कारण था इस अवधि के दौरान निर्यात की तुलना में आयात में आपेक्षिक रूप से वर्ष-दर-वर्ष गिरावट होना। बाह्य माँग की स्थिति के संबंध में विस्तार से चर्चा अध्याय III में की गयी है।

II.17 सभी पहलुओं पर विचार करने से यह पता चलता है कि निजी माँग को समर्थन प्रदान करने के लिए नीतिगत प्रेरक तत्वों की भूमिका के बावजूद समग्र माँग में दुर्बलता बनी रही है। निजी उपभोग माँग में वृद्धि में वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में गिरावट इतनी तेज हुई कि बाद की तिमाहियों में उस स्तर से काफी पुनरुत्थान की उम्मीद ही की जा सकती है। चालू राजकोषीय वर्ष में विस्तारक राजकोषीय नीति के बने रहने, खास कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) के अंतर्गत अधिक व्यय होने और छोटे वेतन आयोग के अंतर्गत दिये जाने वाले शेष बकायों का भुगतान करने, जिससे निजी उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा, के चलते उपभोग में और सुधार होने की भी उम्मीद की जा सकती है। सूखे के कारण कृषिजन्य आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए ग्रामीण व्यय में कमी आ सकती है, लेकिन सरकार द्वारा अगस्त 2009 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से ग्रामीण माँग में किसी गिरावट को कम करने में मदद मिल सकती है। निकट भविष्य में एक अंतराल के साथ निवेश माँग में तेजी आ सकती है, जो उन्नत घरेलू कारोबार रुझान, अनुकूल घरेलू बाजार स्थिति, विश्व पूँजी बाजार में पुनरुत्थान के संकेत और घटते हुए जोखिम प्रीमियम के अनुरूप होगा।